and publishers for producing books of an acceptable standard at reasonable prices for students and teachers of Indian Universities and technical institutes under its scheme for the subsidised publication of books. The books are published in English, Hindi or in any other language listed in the 8th schedule of the constitution.

The books subsidised under the scheme are those for which a definite need is felt and which relate to subject areas where books of an acceptable standard are either not available or are so highly priced to be beyond the means of the majority of students.

The author receives royalty equal to 20% of the published price of the subsidised edition of the book, directly from the Trust, on publication of the book. The publisher is paid 50% of the total cost of production of the book, as subsidy.

Over 800 titles have been subsidised under the scheme since its inception in 1970.

Need to Check Brahmaputra's Floods in Jorhat Town

733. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the river Brahmaputra is now only few kilometers away from the Jorhat town and the only protective measure to check the southward advance of its course is the only embankment at a distance of one Km. from the Nimati Ghat, which is also in danger; and

(b) if so, what action has been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) The Brahmaputra river is about twelve kilometers away from the Jorhat town. At present, the embankment on left bank from Hatisal to Neamatighat-Dainigaon and in downstream of Kokilamukh is providing protection to Jorhat twon from floods in Brahmaputra. The erosion of the left bank on river Brahmaputra at Neamatighat is tending to move southwards towards the embankment and the embankment is presently 1.00 to 1.50 kilometer away from river bank.

(b) To check the shift of Brahmaputra river course in southward direction due to erosion at the Hatisal-Neamatighat areas Government of Assam has submitted to the Union Government in July, 1995 an anti erosion scheme titled 'Protection of Dainigaon-Hatisal-Neamatighat area against the erosion of Brahmaputra river' at an estimated cost of about Rs. 32 crore. The scheme is under appraisal by the Central agencies.

अनिवासी भारतीयों द्वारा इस्पात संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव

734. श्री चिमन भाई हरिभाई शुक्ल: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनिवासी भारतीयों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों से देश के विभिन्न भागों में इस्पात संयंत्र व अन्य संबद्ध इकाइयां स्थापित करने हेतु अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए प्रस्तावों पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) उपर्युक्त प्रस्तावों में से उन प्रस्तावों की संख्या क्या है जिन्हें सरकार ने मंजूर कर दिया है; और

(ङ) प्रत्येक प्रस्ताव में कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है और उन राज्यों के क्या नाम है जहां प्रस्तावित संयंत्र स्थापित किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ङ) निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों और अन्य संबद्ध इकाइयों की स्थापना करने के लिए अप्रवासी भारतीयों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र और अन्य संबद्ध इकाइयां स्थापित करने के लिए अप्रवासी भारतीयों और विदेशी कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा

क्रम सं॰	कम्पनी का नाम तथा स्थान	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम (निवेशक)	विनिर्माण की मद तथा क्षमता	विदेशी साम्या शेयर % तथा परियोजना लागत	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स निप्पोन डेनरी इस्पात लिमिटेड, दोवली राएगढ़, महाराष्ट्र।	मैसर्स इस्पात मेक्सिकाना मैक्सिको।	एच॰आर॰ कवायलें 10 लाख टन वार्षिक	25%(150 करोड़ रुपये) परियोजना लागत 2200 करोड़ रुपये (अनुमानित)	सरकार द्वारा मंजूर
2.	मैसर्स आरिन्ड स्टील्स लिमिटेड क्योंझर उड़ीसा (दैतारी में चरण-1)	मैसर्स गोल्ड स्टार इन्वेस्टमेंट लिमिटेड), दुबई, यू एस एस इंजीनियर्स एण्ड कंसल्टेन्टस इंक, यू एस ए	हाट एण्ड कोल्ड कवायलें / शीट आदि क्षमता-7,00,000 टन वार्षिक (सी आर सी-चरण-1) 10,00,000 टन वार्षिक (एच आर सी / सी आर सी-चरण-II)	44.44% (400 करोड़ रु॰) परियोजना लागत 1650 करोड़ रुपये (646 करोड़ रुपये चरण-1 के लिए)	सरकार द्वारा मंजूर।
3.	मैसर्स मिड-ईस्ट इन्टीग्रेटिड स्टील लिमिटेड, कलिंगा नगर इण्डस्ट्रियल कम्पलैक्स जाजपुर, उड़ीसा।	मैसर्स चीन मेटलर्जिकल इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन, चीन।	कच्चा लोहा 0.40 लाख टन वार्षिक, इस्पात स्लाब तथा छड़ें और स्ट्रक्चरल 4.10 लाख टन वार्षिक (100% निर्यातोन्मुखी)	(क) 9% (25 करोड़ रुपये) (ख) अप्रवासी भारतीय 25 करोड़ रुपये परियोजना लागत (691.85 करोड़ रु॰)	सरकार द्वारा मंजूर
4.	मैसर्स मिड-ईस्ट इन्टीग्रेटिड स्टील लिमिटेड, कलिंगा नगर इण्डस्ट्रियल कम्पलैक्स जाजपुर, उड़ीसा।	मैसर्स चीन मेटलर्जिकल इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन चीन।	कच्चा लोहा 2.0 लाख टन वार्षिक, इस्पात स्लाब तथा स्ट्रक्चरल इस्पात 10 लाख टन वार्षिक (शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी)	(क) 20.4% (100 करोड़ रु॰) (ख) अप्रवासी भारतीय 78 करोड़ रुपये परियोजना लागत 147 करोड़ रु॰	सरकार के विचाराधीन
5.	मैसर्स मेसलेकलिंगा स्टील लिमिटेड, कलिंगा नगर इण्डस्ट्रियल कम्पलैक्स जिला जाजपुर, उड़ीसा	मैसर्स डेण्डसली एण्ड कम्पनी, इटली, यूनाइटेड इंजीनियरिंग इंक. यू एस ए सानसाग कारपोरेशन कोरियाबिमिसुई एण्ड कम्पनी जापान	एच आर कवायल 13 लाख टन वार्षिक कच्चा लोहा 50 लाख टन वार्षिक (100% निर्यातोन्मुखी)	12.5% (115 करोड़ रु॰) एन आर आई साम्या (रिपेट्रीएबिल) 20%) 183 करोड़ रु॰) कुल परियोजना लागत 2746 करोड़	सरकार द्वारा मंजूर

1	2	3	4	5	6
6.	मैसर्स श्रीमुख टील लिमिटेड, गांव-कुरिवाला तालुक-ओलपाड़जिला-सूरत राज्य-गुजरात	एन आर आई	इलेक्ट्रोड क्वालिटी वास पर एक 75,000 टन वार्षिक	24% (75.00 लाख रुपये)	सरकार द्वारा मंजूर
7.	मैसर्स नागार्जुन कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाईजर्स लि॰ कनारा, मंगलौर कर्नाटक।	एन आर आई	एन आर कॉरपस-2.2 एम॰टी॰पी॰ए॰ (100% ई॰ओ॰यू॰)	10% (80 करोड़ रुपये)।	सरकार के विचाराधीन
8.	मैसर्स मिड-ईस्ट इंटीग्रेटिड स्टील लि॰, कलिंगा, नगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ललित खा।	मैसर्स चाइना मैटेलर्जिकल ग्रुप इंपोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन, चाइना	पिग आयरन कैप 0.464 एम॰ टी॰ पी॰ ए॰	4.55% (538.3 लाख रु॰) एन आर आई होल्डिंग 1846.36 लाख रुपये परियोजना लागत 220 करोड़ रुपये विखाइड 307 करोड़ रुपये।	सरकार द्वारा मंजूर
9.	मैसर्स लैको-फैरो लि॰ ग्राम पंचगुनेरी, जिला-चित्तूर, आं॰प्र॰।	एशियन फाइनेंस एण्ड इनवेस्टमैंट कारपोरेशन लिमिटेड सिंगापुर।	पिग आयरन कैप 90,000 टी॰पी॰ए॰	10.15% (2.32 करोड़ रु॰) +एन॰ आर॰ आई॰ होल्डिंग 22.88%) 500 लाख रुपये)	सरकार द्वारा मंजूर
10.	मैसर्स ताता इंटरनेशनल कोपोरेटी, जिला-रैजाद महाराष्ट्र।	मैसर्स एफ॰के॰आर॰एल लि॰ जापान।	प्रोसेस्ड क्रैप — 12000 टी॰पी॰ए॰	23.08% (6 लाख रुपये) परियोजना लागत 87 लाख रुपये	सरकार द्वारा मंजूर
11.	मैसर्स कोस्को क्रैप रीसाल इंडिलंग (प्रा॰) लि॰, महुवा, भावनगर गुजरात।	एन॰आर॰आई॰	प्रोसेस्ड क्रैप 12000 टी॰पी॰ए॰	25% (6.25 लाख) परियोजना लागत 66 लाख रुपये।	सरकार द्वारा मंजूर
12.	मैसर्स फलेवर इंडिया लि॰ मगईमल्लाल नगर, डिंगलल पट्टू तमिलनाडू।	एन॰आर॰आई॰	प्रोसेस्ड क्रैप 35000 टी॰पी॰ए॰	3% (10 लाख रुपये)	सरकार द्वारा मंजूर
13.	मैसर्स निजीमैन कारपोरेशन सोसिया, गुजरात।	प्रमुख भागीदारी सहित निजीमैन कारपोरेशन द्वारा प्रवर्तित विदेशी स्वामित्व का संयुक्त उद्यम।	शिपब्रेकिंग ऑपरेशंस ऑफ सी॰ एल॰ सी॰ एस॰ एण्ड ओ॰ एल॰ सी॰ सी॰ एस॰ 3-4 एल॰ डी॰ टी॰	6.41 करोड़ रुपये।	सरकार द्वारा मंजूर
14.	मैसर्स नव नैरिन प्रा॰ लि॰ अलंग, गुजरात।	मैसर्स अज्रोव शिपिंग कंपनी लाईन	शिपब्रेकिंग, शिप बिल डिंग एण्ड शिप रिपेयल सें 4.0 मिलियन एल॰डी॰टी॰	30 लाख रुपये	सरकार द्वारा मंजूर
15.	मैसर्स प्रतीक शिपब्रेकर्स प्रा॰ लि॰ सोसिया, गुजरात।	एन॰आर॰आई॰	शिप ब्रेकिंग इत्यादि	51 लाख रुपये	सरकार के विचाराधीन

1	2	3	4	5	6
16.	मैसर्स पोलीवाटिक स्टील लिमिटेड।	इण्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट्स प्रा॰ लि॰	सिम्प्रोलिंग ऐरोसिंग, कैल्शियम के लिये आक्सीजन गैस के उत्पादन।	584.64 लाख रूपये प्रत्यावर्तनीय आधार पर एन॰आर॰आई॰ के 144 लाख रूपये के निवेश सहित।	सरकार के विचाराधीन
17.	मैसर्स स्वामीनारायण सिमेन्ट लिमिटेड प्रा॰ लिमिटेड	श्री मनसुख वल्लभदास भाई पटेल, एन॰आर॰ आई॰ कम्पनी के एक निदेशक	सिम्प्रोलिंग, क्लिंप-रिपेयरिंग इत्यादि।	2.55 करोड़ रूपये	सरकार के विचाराधीन
18.	मैसर्स सेसा केम्बलस कोक एण्ड गोवा प्रा॰ लि॰ आंटोरिनया	मैसर्स केम्बलस कोल कंपनी लि॰, अमलेन, गोल आ।	नवीन एकीकृत अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स 2.8 लाख वार्षिक चरण-I	40% (10 करोड़ रुपये) परियोजना लागत 65 करोड़ रुपये परिकल्पित (चरण-I)।	सरकार द्वारा मंजूर

Entitlement of MPs, MLAs and Ex-MPs for Preferential DDA Allotment

735. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether MPs, MLAs and Ex-MPs are entitled for preferential or out of turn allotment of houses sites in Delhi, by DDA;

(b) whether bulk land or Houses were allotted to MPs or MLAs Cooperative Housing Society by DDA during 1992-93, 1993-94 and 1994-95, if so; the details thereof; and

(c) if not, whether Government will consider allotment of sites or houses by DDA to MPs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS EMPLOYMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) It is not possible to provide any preferential treatment to MPs, Ex-MPs and MLAs keeping in view the fact that DDA has to cater to the requirements of large number of registrants who have been awaiting allotment of flats for a long time.

Marketing Strategies for Coconut

736. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme for 1995-96 for better marketing strategies for coconut farmers of Andhra Pradesh;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any consultation has taken place with Andhra Pradesh Government in this regard; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b) There is no specific scheme for 1995-96 for better marketing strategies for coconut farmers of Andhra Pradesh. However, Coconut Development Board extends promotional support like linking the supplier and potential buyers, make available market review and reports. The